योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति

(3.1) भवन निर्माण विभाग के वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक योजना रू0 24843.520 लाख के लिए स्वीकृत है, जिसमें न्याय प्रशासन के कार्यो के लिए रू0 200.00 लाख रूपये का प्रावधान है।

(3.2) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना के अंतर्गत विधान मंडल एवं सचिवालय विस्तार की योजना, अन्तर्राष्ट्री कन्वेंशन सेन्टर पटना, भभुआ, पटना एवं सासाराम में निरीक्षण भवन की योजना का कार्यान्वयन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में किया जा रहा है।

(3.3) इसके अतिरिक्त योजना मद् से विभिन्न आवासीय/गेर आवासीय भवनों में अतिरिक्त निर्माण कार्य की योजना की स्वीकृति दी गयी है एवं कार्य प्रगति में है। इन कार्यो को भी वर्तमान वित्तीय वर्ष मे पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(3.4) भवन निर्माण विभाग द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के भवन निर्माण संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है एवं इनसे संबंधित उपलब्धि को संकलित किया गया है जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है।

3.5.1 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पॉलिटेक्निक

क) राजकीय पॉलिटेक्निक मुंगेर, मधेपुरा, सुपौल, भभुआ, बांका, सीतामढ़ी, समस्तीपुर पॉलिटेक्निक का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।

ख) राजकीय पॉलिटेक्निक, अस्थावां, गोपालगंज, शेखपुरा, सिवान, अररिया, नवादा, बक्सर, टिकारी (गया) में कार्य प्रगति पर है।

ग) औरंगाबाद, खगड़िया एवं बेतिया में राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है।

अभियंत्रण महाविद्यालय

क) पुर्णियां, बांका बेगुसराय, सहरसा, बख्तियारपुर, जमुई, सुपौल एवं कटिहार का कार्य प्रारंभ है।

ख) शेरशाह सूरी अभियंत्रण महाविद्यालय-सासाराम शेखपुरा, हाजिपुर (वैशाली), बक्सर, आरा, मधेपुरा एवं सीतामढ़ी का कार्य प्रारंभ किया जाना है।

ग) अभियंत्रण महाविद्यालय कैमुर एवं पश्चिम चम्पारण के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है।

3.5.2 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

क) बुद्धा समयक दर्शन एवं स्मृति स्तुप निर्माण का मुल कार्य प्रारंभ करना है।

ख) बिहार संग्रहालय का कार्य पूर्ण कर इसे उपयोग में लाया जा रहा है।

ग) राजगीर स्पोर्टस एकेडमी एवं क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए कार्रवाई की जा रही है।

घ) छपरा, मुंगेर, जमुई एवं बक्सर मे नया संग्रहालय भवन का कार्य पूर्ण है।

ड.) सिताब दियारा में स्मृति भवन एव पुस्तकालय का निर्माण कार्य पूर्ण है।

3.5.3 ग्रामीण विकास विभाग

क) रू0 226.88 करोड़ की लागत पर 26 प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय-सह-आवास एवं रू0 71.41 करोड़ की लागत पर 12 प्रखंडों में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा रू0 473.85 करोड़ की लागत से स्वीकृत 39 प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय-सह-आवास के विरूद्ध स्थल उपलब्धता के आलोक में कार्यों के क्रियान्वयन की कार्रवाई की जा रही है।

ख) आर.आई.डी.एफ. XXI योजनान्तर्गत चयनित 101 प्रखंडों में प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र के निर्माण हेतु रू0 93547.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसमें से 85 प्रखंडों में कार्य प्रारंभ है।

3.5.4 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

क) रू0 273.00 करोड़ की लागत से एम.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत विभिन्न मदरसा/मध्य/प्राथमिक/उच्च विद्यालय में अतिरिक्त कमरे/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं छात्रावास (50 तथा 100 शैय्यावाले) का निर्माण पूर्णियां, कटिहार, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा एवं बेतिया में किया जा रहा है।

ख) सीमामढ़ी में पॉलिटेक्निक का निर्माण कार्य पूर्ण है।

ग) किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के नीजागाछ में रू0 43.36 करोड़ की लागत से पॉलिटेक्निक निर्माण कार्य पूर्ण है।

घ) पटना, भागलपुर, एवं मोतिहारी में अल्पसंख्यक बालिका/बालक छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण है एवं मधेपुरा, गया में कार्य प्रगति में है।

ड.) सासाराम एवं गया में अल्पसंख्यक बालक/बालिका छात्रावास निर्माण कार्य पूर्ण है।

3.5.5 श्रम संसाधन विभाग

i. सात निश्चय के तहत कुल सामान्य एवं महिला सहित 36 आई0टी0आई0 की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। सभी योजनाओं का कार्य प्रगति में है।

ii. सात निश्चय के पूर्व कुल 24 स्वीकृत योजनाएँ (महिला सहित) है जिसमें कि अररिया, अरवल, छपरा, शिवनगर (मधुबनी), महकार (गया), टेकारी (गया) एवं महिला आई0टी0आई0 सुपौल का कार्य पूर्ण है एवं बाकी कार्य प्रगति में है।

iii. एल0डबलु0ई0 के तहत कुल 6 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है एवं सभी योजनाओं का कार्य प्रगति में है।

iv. संयुक्त श्रम भवन की कुल स्वीकृत योजनाएं 16 है, सभी कार्य प्रगति में है।

3.5.6 समान्य प्रशासन विभाग

i. प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, गया एवं बिहार लोक सेवा आयोग अन्तर्गत (जी0+1) का निर्माण कार्य प्रगति में है।

ii. लखीसराय, सहरसा, बांका, सिवान, मुजफ्फरपुर, सुपौल जिलान्तर्गत अतिरिक्त अतिथि गृह का निर्माण कार्य प्रगति में हैं तथा जहानाबाद, अररिया एवं मधुबनी का कार्य पूर्ण है।

3.5.7 विधि विभाग

i. पटना उच्च न्यायालय विस्तारीकरण का कार्य प्रगति में।

ii. अनुमंडलीय कोर्ट भवन पुर्णियाँ, दानापुर, नवगछिया(भागलपुर), नालंदा का कार्य पूर्ण एवं मंझौल (बेगुसराय) 10 कोर्ट भवन, लखीसराय एवं 10 कोर्ट भवन मसौढ़ी (पटना) का कार्य प्रगति में है।

iii. कुल 8 जिला कोर्ट भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जिसमें कि किशनगंज, बांका, दरभंगा एवं मोतिहारी का कार्य पूर्ण तथा 12 जिला कोर्ट भवन, बेगुसराय, 10 जिला कोर्ट भवन आरा, 10 जिला कोर्ट भवन, सिवान एवं 10 जिला कोर्ट भवन, छपरा कार्य प्रगति में है।

3.5.8 कृषि विभाग

जमुई जिला में कृषि भवन का निर्माण कार्य पूर्ण है तथा संयुक्त कृषि निदेशक के कार्यालय, सहरसा का निर्माण कार्य एवं औरंगाबाद कृषि कार्यालय के अवशेष कार्य का निर्माण कार्य प्रगति में है।

3.5.9 परिवहन विभाग

जिला परिवहन कार्यालय का निर्माण, अररिया एवं अरवल का कार्य पूर्ण है एवं लखीसराय तथा मधेपुरा का कार्य प्रगति में है।

3.5.10 निबंधन एवं उत्पाद विभाग

निबंधन एवं उत्पाद विभाग के अंतर्गत कुल स्वीकृत योजनाओं की संख्या 19 है, जिसमें 5 का कार्य पूर्ण है एवं बाकी का कार्य प्रगति में। इसके अंतर्गत अवर निबंधन कार्यालय एवं आवासीय भवनों का कार्य कराया जा रहा है।

3.5.11 वित्त विभाग

वित्त विभाग के अन्तर्गत कुल 16 स्वीकृत योजनाएँ है, जिसमें 07 योजनाओं का कार्य पूर्ण है एवं बाकी 09 योजनाओं का कार्य प्रगति में है। इसके अंतर्गत कोषागार भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराया जा रहा है।

3.5.12 वाणिज्य कर विभाग

वाणिज्य कर विभाग के अन्तर्गत कुल 16 स्वीकृत योजनाएँ है, जिसमें 07 योजनाओं का कार्य पूर्ण एवं बाकी 09 योजनाओं का कार्य प्रगति में है। इसके अंतर्गत वाणिज्य कर अंचल कार्यालय एवं आवासीय भवनों का कार्य कराया जा रहा है।

3.5.13 **पशु एवं मतस्य संसाधन विभाग**

राज्य में विभन्न स्थानों पर प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय भवन तथा अनमुमंडल पशु अस्पताल भवनों का निर्माण कराया जा रहा है।

3.5.14 **राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

राज्य के 38 जिलों में स्वीकृत 493 डाटा केन्द्र-सह-आधुनिक अभिलेखागार के निर्माण कार्य के विरूद्ध 351 का कार्य पूर्ण है तथा शेष में स्थल उपलब्धता के आलोक में कार्य प्रगति में है।

3.5.15 **खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग**

423 गोदामों के निर्माण की स्वीकृति के विरूद्ध 500/1000/2000 मे0 टन के 380 गोदामों का निर्माण रू0 167.86 करोड़ की लागत पर किया गया है।

3.5.16 **अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग**

अनुसूचित जाति एवं जनजाति आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास की मरम्मती हेतु स्वीकृत योजनाओं का कार्य पूर्ण कराया गया है।

3.5.17 **योजना एवं विकास विभाग**

38 जिलों में निबंधन-सह-परामर्श केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। चहारदिवारी एवं बैरक निर्माण का कार्य पूर्ण करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।